

**भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2738
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024**

बीएसएनएल के पुनरुद्धार की स्थिति

2738. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए घोषित किए गए पुनरुद्धार पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;

(ख) बीएसएनएल की अवसंरचना के उन्नयन, विशेषकर 4जी और 5जी सेवाओं को शुरू करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रचालनात्मक सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऋण की पुनर्संरचना और कर्मचारियों के कल्याण सहित बीएसएनएल की वित्तीय देयताओं का समाधान करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में किफायती और विश्वनीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में बीएसएनएल की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(च) क्या सरकार बीएसएनएल की दीर्घकालिक वित्तीय सततता और निजी ऑपरेटरों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों की खोज अथवा उनका कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो ऐसी कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (च) मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुज्जीवन पैकेज को 23.10.2019, 27.07.2022 और 07.06.2023 को मंजूरी दी। पुनरुज्जीवन पैकेजों में मुख्य रूप

से अनुग्रह राशि के लिए भारत सरकार द्वारा बजटीय आबंटन की सहायता से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से कर्मचारी लागत के यौक्तिकीकरण, सॉवरेन गारंटी बॉण्ड जुटाकर ऋण की पुनर्संरचना, बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन के लिए नये पूंजी निवेश, 4जी/5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन पुनरुज्जीवन उपायों और बीएसएनएल की कार्यनीति और सेवाओं के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने अपनी प्रचालन लागत को कम कर लिया है और 2020-21 से प्रचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

पुनरुज्जीवन पैकेज के तहत आवंटित कुल धनराशि 2,28,166.96 करोड़ रुपये है, जबकि संवितरित धनराशि 1,33,581.08 करोड़ रुपये है।

आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, बीएसएनएल ने अखिल भारतीय तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4जी साइटों के लिए क्रय आदेश दिया है। सितंबर 2023 से 4जी उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो गई है और 06.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 61,492 4जी साइट संस्थापित की गई हैं और 51,135 साइटें ऑन-एयर हैं। 4जी उपकरण 5जी में अपग्रेड करने योग्य है।

सेवा से वंचित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, सरकार डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रही है। बीएसएनएल को सौंपी गई ऐसी परियोजनाओं में 4जी सेचुरेशन, सीमा चौकियां (बीओपी)/सीमा आसूचना चौकी (बीआईपी), वामपंथी उग्रवाद (चरण-1), लक्षद्वीप द्वीपसमूह में दूरसंचार अवसंरचना का उन्नयन और संवर्धन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान करने सहित सभी ग्राम पंचायतों में और मांग के आधार पर गांवों में फाइबर के विस्तार के लिए 1.39 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को मंजूरी दी गई है। बीएसएनएल इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।
